(ग) इन आरोपों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) :

(क) जी हां ।

(ख) 1978–79, 1985–86 तथा 1986–87 के संबंध में भारत के महालेखापाल तथा नियंत्रक की रिपोर्ट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के कुछ पहलुओं पर टिप्पणी की गई है जिसमें से कुछ पर दिनांक 19–3–1990 के डक्कन हैराल्ड में प्रकाशित समाचार में प्रकाश डाला गया था । इनमें से कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं :—

1. माध्यमिक स्कूल अध्यापक तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षक के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता ।

2. माध्यमिक स्कूल अध्यापकों तथा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को अद्यतन बनाने के लिए स्थापित सतत शिक्षा केन्द्रों का असंतोषजनक कार्यकरण ।

3. अनबिकी पुस्तकों तथा पर्याप्त मूल्यों के अप्रचलित शीर्षकों का संचय ।

4. अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण करने में विलंब ।

(ग) महालेखापाल तथा नियंत्रक की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने के लिए एक सुनिर्धारित पद्धति है और सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों से इस पद्धति का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

थलसेना/नौसेना/वायुसेना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों का प्रतिशत

1378. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थलसेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों का वर्तमान प्रतिशत क्या है ; और

(ख) सशस्त्र बलों में उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) भारत के सभी योग्य नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, वंश, समुदाय या धर्म के हों, चयन मानदण्ड के आधार पर सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में भर्ती हो सकते हैं । अतः सेनाओं में किसी जाति, जनजाति या समुदाय के लिए कोई आरक्षण कोटा नहीं रखा गया है । सेनाओं में संक्रियात्मक कार्यकुशलता यथासंभव उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए भर्ती की वर्तमान पद्धति को जारी रखना अपेक्षित है ।

गंगा कार्य योजना के अधीन वाराणसी में खर्च की गयी धनराशि

1379. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"गंगा कार्य योजना" के अधीन वाराणसी और इलाहाबाद में जल प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वाराणसी और इलाहाबाद में स्कीमों पर मार्च, 1990 के अन्त तक क्रमशः रु० 30.15 करोड़

और रु० 13.44 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है । इलाहबाद में 18 संस्वीकृत स्कीमों में से 13 पूरी की जा चुकी है । इनमें, 8 अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन की स्कीमें, 2 अल्प-लागत स्वच्छता कार्यक्रम, 1 नदी तटाग्र सुविधा और 2 अन्य स्कीमें शामिल हैं । अन्य बातों के साथ-साथ स्कीमों के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप इस नदी में बहने वाले 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन, अपशेष जल को नदी मे प्रवाहित होने से अवरोधित कर दिशा-परिवर्तित कर दिया गया है तथा 58 सामुदायिक शौचालय परिसरों की स्थापना की गई है । इलाहाबाद में इन स्कीमों के पूरा हो जाने के कारण ही कुंभ मेले के दौरान प्रदूषण-मुक्त संगम स्नान सम्भव हो सका । वाराणसी में 35 संस्वीकृत स्कीमों में से 25 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं । इनमें से 7 अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की स्कीमें, 2 सीवेज उपचार संयंत्र, 3 अल्प-लागत स्वच्छता कार्यक्रम, 3 नदी तटाग्र सुविधाएं तथा 10 अन्य स्कीमें शामिल है । इन स्कीमों के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ इस नदी में गिरने वाले 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन अवशेष जल को गंगा में प्रवाहित होने से अवरोधित एवं दिशा-परिवर्तित किया गया है और 62 सामुदायिक शौचालयों की स्थापना की गई है ।

Introduction of subjects in Humanities in some kendriya Vidyalayas of Delhi

1380. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce subjects in humanity in the Kendriya Vidyalayas in Pitampura, Shalimar Bagh, Lawrence Road and Sainik Vihar in Delhi during current session;

(b) if so, what are the details thereof and the steps taken so far in this regard; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) In accordance with the existing policy of the Sangathan, the question of introduction of a new stream is considered only after the X class results of the year are declared provided a minimum of 20 students need a particular stream and if Physical facilities like class-rooms, laboratories etc. are available. Kendriya Vidyalaya, Lawrence Road is already having the Humanities stream. The question of opening Humanities stream in Kendriya Vidyalayas at Shalimar Bagh and Sainik Vihar can be considered only if proposals are received after class X results. Kendriya Vidyalaya, Pitampura is being upgraded upto class X during the current session and as such the question of introduction of any stream at this Vidyalaya during this academic year does not arise.

Non-payment of salaries to the staff by recognised and aided schools in Delhi

1381. SHRIMATI MIRA DAS:
DR. BAPU KALDATE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some Government recognised and Government aided schools in Delhi do not pay salaries to their staff regularly;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether it is a fact that some schools have deducted income tax dues from the unpaid salaries of the teachers in spite of their declaration, duly supported by documents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) One such case in respect of Baba